दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 22.09.2009

निर्णय की तिथि : 25.09.2009

आप.अ. सं. 207/2009

सुखदेव सिंह ... ... अपीलकर्ता

द्वारा: श्री के.के. सूद, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कुणाल मल्होत्रा और सुश्री दीया डिसूज़ा, अधिवक्तागण।

- बनाम -

राज्य ... ... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री पवन शर्मा, अधिवक्ता।

और

आप.अ. सं. 220/2009

हरि सिंह राणा और अन्य ... ... अपीलकर्ता

द्वारा : श्री के.बी. एंडली, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री एम.एल. यादव, अधिवक्ता।

- बनाम -

राज्य... ... ... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री पवन शर्मा, अधिवक्ता।

कोरम:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत भरीहोक

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के रिपोर्टर को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां

2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हां

3. क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए? हां

संजय किशन कौल, न्या.

1. निर्माण के लिए एक भूखंड की नींव की खुदाई के परिणामस्वरूप विवाद हुआ और इसके उग्र होने के कारण मृतक सुरेंद्र नाथ पांडे की हत्या का आरोप लगाया गया है।

2. 20.10.2003 की सुबह एक घटना हुई जब मृतक और अपीलार्थियों के बीच लड़ाई हुई। मृतक ने भूखंड में नींव खोदने के लिए अपीलकर्ताओं का विरोध किया। डी.डी. प्रविष्टि सं. 4-ए (प्र. अभि.सा. -18/ए) के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ और एच.सी. धरम प्रकाश को घटना स्थल का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया और घटना स्थल पर मामले को नियंत्रण में लाया गया और निर्माण रोक दिया गया। लेकिन यह विवाद फिर से पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुआ जब डीडी नंबर 11-ए (प्र. अभि.सा. - 18/बी) के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई परिणामस्वरूप एचसी धरम प्रकाश दूसरी बार वहां गया, जिन्होंने पाया कि अपीलकर्ताओं ने फिर से खुदाई की गतिविधि शुरू कर दी है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला है कि उसी दिन पुलिस स्टेशन में सूचना मिली थी कि मृतक को 35 प्रतिशत जली हुई हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह जानकारी ड्यूटी कॉन्सटेबल सुनील कुमार, सफदरजंग अस्पताल द्वारा भेजी गई थी और

पु. स्टे. एस.एन. पुरी में डी.डी. सं. 42बी (प्र. अभि.सा.- 13/ए) के रूप में अभिलिखित की गई थी।

4. एम.एल.सी. (प्र. अभि.सा.-14/ए) मृतक सुरेंद्र नाथ पांडे के प्रवेश का समय अपराह्न 12.10 बजे दर्शाता है। मृतक को उसकी भतीजी सुश्री माया द्वारा भर्ती कराया गया था। एम.एल.सी. ने अभिलिखित किया है कि जलना मृतक के तीन व्यक्तियों के साथ झगड़े का परिणाम बताया गया है जिन्होंने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। मृतक की स्थिति गंभीर, सचेत और उन्मुख के रूप में अभिलिखित की गई थी, लेकिन निर्जलीकरण (+ + +) था। एस.आई. युध बीर सिंह अस्पताल पहुंचे और प्र.अभि.सा. 15/ए के अनुसार मृतक का बयान अभिलिखित करने की अनुमति मांगी। डॉक्टर ने राय दी कि रोगी होश में था और बयान देने के लिए उन्मुख था। मृतक का बयान अभिलिखित किया गया था, जिससे पता चलता है कि मृतक बेहतर महसूस करने के बाद ही घटना के बारे में अपना बयान देना चाहता था। यह बात मृतक ने अपनी पत्नी और सुश्री माया सहित तीन अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति में कही क्योंकि उसे लगा कि वह इतना ठीक नहीं है। मृत्युकालिक कथन (प्र. अभि.सा.-15/डी) को एस.आई. युध बीर सिंह द्वारा 21.10.2003 को पूर्वाह्न 9:30 बजे रिकॉर्ड किया गया था। इस कथन के संदर्भ में, मृतक डेयरी का व्यवसाय कर रहा था जबकि अपीलार्थी उसके पड़ोसी थे। यह कहा गया है कि मृतक और अपीलार्थियों के बीच अतीत में विवाद हुए थे और जब मृतक ने 20.10.2003 को अपीलार्थियों को खुदाई करने से रोकने की कोशिश की, तो अपीलार्थी गुस्से में आ गए, विशेष रूप से जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया था। कहा जाता है कि अपीलकर्ता हरि सिंह राणा ने सुखदेव सिंह के कहने पर मिट्टी के तेल की एक बोतल लाई और उसे मृतक के ऊपर डाल दिया। मृतक को रेलवे लाइन की ओर घसीटा गया और मृतक पर एक जलता

हुआ माचिस की तीली फेंक दिया गया। मृतक के चिल्लाने पर, अपीलकर्ता भाग गये। मृतक की आवाज़ सुनकर उसकी भतीजी सुश्री माया अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाई, जिसके बाद सुश्री माया ने मृतक को अस्पताल पहुंचाया। मृतक ने कहा कि उसने पहले बयान नहीं दिया था क्योंकि वह दर्द में था। मृतक का निधन 21.10.2003 को अपराह्न 10.40 बजे हुआ।

5. प्राथमिकी संख्या 421/2003 भा.दं.सं. की धारा 307/34 के तहत पुलिस स्टेशन एस.एन. पुरी में 21.10.2003 को अभिलिखित की गई थी, जिसे भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत एक में बदल दिया गया था। अपीलार्थियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ सहपठित 34 के तहत आरोप तय किया गया था। अपीलकर्ताओं ने खुद को निर्दोष बताया और विचारना का दावा किया।

6. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से इस मृत्युकालिक कथन और अभि.सा. 3 श्री प्रमोद कुमार ठाकुरई (मृतक की पत्नी का भाई) की गवाही पर आधारित है एक चश्मदीद गवाह के रूप में, जिसकी गवाही को विचारण न्यायालय द्वारा भी ज्यादा विश्वसनीयता नहीं दिया गया है। यह भी देखा जा सकता है कि मृतक की भतीजी सुश्री माया को गवाह के कठघरा में पेश नहीं किया गया था और अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसका कारण यह है कि जां.अधि. को मृतक की पत्नी ने सूचित किया था कि वह पक्षद्रोही हो गई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाया कि मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था (प्र. अभि.सा.-15/डी), जिसे आसपास की परिस्थितियों से पर्याप्त रूप से पुष्ट पाया गया और अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, दिनांक 03.03.2009 के निर्णय के द्वारा उन्हें

आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को रु.5,000/- का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई, जो दिनांक 12.03.2009 के सजा पर आदेश के संदर्भ में छह महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरने के लिए है, जिसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

7. अपीलकर्ताओं ने अपने बचाव में तीन साक्षी को पेश किया था जिन्होंने गवाही दी है कि मृतक की पत्नी और मृतक के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक ने पूर्वाह्न लगभग 11.30 बजे अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला, जिसके बाद उसने माचिस की तीली को जलाया और खुद को आग लगा ली। इस प्रकार, अपीलार्थियों का बचाव यह है कि यद्यपि मृतक जल गया था, लेकिन वे मृतक द्वारा स्वयं उसके और उसकी पत्नी के बीच कटुता के कारण मिट्टी का तेल डालने के कारण हुए थे और अपिलार्थियों पर दोष मढ़ने की मांग की गई थी।

8. 20.10.2003 को हुए विवाद को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने एच.सी. धरम प्रकाश से अभि.सा.-1 के रूप में पूछताछ की। अन्य भौतिक गवाह मृतक की पत्नी श्रीमती सत्यभामा हैं जो गवाह के कठघरा में अभि.सा.-2 के रूप में उपस्थित हुईं। उन्होंने पहले के विवाद के बारे में गवाही दी, जिसके बाद वह मृतक की सलाह को देखते हुए स्थानीय विधायक के पास गई और उनसे हस्तक्षेप की मांग की, क्योंकि उनके अनुसार अपीलकर्ताओं ने उनके पति को धमकी दी थी। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता/अभियुक्त श्री रमजानी उर्फ रमजान मोहम्मद के साथ कोई पूर्व झगड़ा नहीं था और न ही उनके साथ कोई विवाद था। अन्य भौतिक गवाह अभि.सा.-3, श्री प्रमोद

कुमार ठाकुरई हैं, जिन्हें चश्मदीद गवाह बताया गया है और जो अभि.सा.- 2 का भाई है। उन्होंने दावा किया कि मृतक और अपीलार्थियों के बीच पहले भी झगड़े हुए थे, हालांकि वे ऐसी घटनाओं की संख्या नहीं बता सके, जो नवंबर, 2002 और जनवरी, 2003 के बीच हुई थीं। आक्षेपित निर्णय के पैरा 40 में, यह देखा गया है कि अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य ने मृतक और अपीलार्थियों के बीच पूर्व विवाद के अस्तित्व को स्थापित किया है। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि अभि.सा.-2 की गवाही के अलावा, पूर्व सिविल विवाद के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। यहां तक कि अभि.सा.-2 ने भी अपनी गवाही में कहा कि मृतक और अपीलकर्ता हरि सिंह राणा के बीच पहले से सिविल विवाद था।

9. वर्तमान अपीलों में जांच किए जाने वाले महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या अभि.सा.-3 को एक चश्मदीद गवाह कहा जा सकता है और क्या उसकी गवाही जांच के दायरे में आएगी। उक्त गवाह ने कहा है कि वह पिछले 14-15 वर्षों से मृतक के साथ रह रहा था और तीनों अपीलार्थियों को जानता था। उसने 20.10.2003 को मृतक के घर पर मौजूद होने का दावा किया जब विवाद पैदा हुआ। उसने प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि वह उस जगह से 20 से 25 फीट की दूरी पर अपनी भैंसों को नहलाने में व्यस्त था, जहां कथित तौर पर मृतक पर मिट्टी का तेल डाला गया था और जब उसने शोर सुना कि मृतक को आग लगा दी गई है तो वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। जिस स्थान पर वह अपनी भैंसों को नहला रहा था वहां से घटना स्थल तक करीब 2-3 मोड़ थे।

10. इस गवाह की गवाही को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अस्वाभाविक होगा कि मृतक के साले ने मृतक को अस्पताल नहीं पहुंचाया, अगर वह वहां मौजूद था,

जबकि मृतक की भतीजी मृतक को अस्पताल ले गई थी। घटना के समय अभि.सा.-3 का कोई बयान अभिलिखित नहीं किया गया था, हालांकि उन्होंने दाह संस्कार के समय मौजूद होने का दावा किया था। 21 दिन बाद उसका बयान अभिलिखित किया गया। इस संबंध में इस गवाह द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि वह मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने गाँव गया था। विचारण न्यायालय ने देखा है कि उक्त गवाह के प्रवेश से यह परिलक्षित होता है कि वह वास्तव में घटना के समय मौजूद नहीं हो सकता है और हो सकता है कि बाद में मृत्युकालिक कथन की रिकॉर्डिंग के लिए आया हो, लेकिन मृत्युकालिक कथन को आसपास की परिस्थितियां पर्याप्त रूप से पुष्टि करती है।

11. इस गवाह की गवाही की जांच करने पर, हम अभि.सा.-3. द्वारा जो कहा गया है, उस पर विश्वास करने में असमर्थ हैं। वह मृतक का असली साला है जो मृतक की पत्नी का भाई है। उसने घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर होने का दावा किया, लेकिन घटना की शुरुआत में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन दावा किया कि आग लगाए जाने के बाद मृतक की चीख-पुकार सुनकर वह वहां पहुंचा था। उक्त गवाह मृतक को अस्पताल नहीं ले गया, लेकिन मृतक की भतीजी को आवश्यक कार्य करने दिया। इसके बाद भी वह दो दिनों तक अस्पताल नहीं पहुंचे जब मृतक को भर्ती किया गया और न ही उनका बयान अभिलिखित किया गया। वह लगभग तीन सप्ताह तक दाह संस्कार के बाद गायब रहा, जिसके बाद उनका बयान अभिलिखित किया गया। अभि.सा.-3 का आचरण उस व्यक्ति के स्वाभाविक आचरण के विपरीत है जो मृतक के साथ निकट संबंध से जुड़ा हुआ था। यह कारक इस गवाह के बयान को अभिलिखित करने में देरी और उसके बयान के साथ मिलकर इस गवाह की गवाही को अविश्वसनीय बनाता है। मृत्युकालिक कथन में मृतक (प्र. अभि.सा.-15/डी) ने अपनी भतीजी द्वारा उसे अस्पताल ले जाने का उल्लेख किया है, लेकिन

अभि.सा.-3 का नाम उस व्यक्ति के रूप में नहीं लिया है जिसने उसकी देखभाल किया था। जहाँ तक अभि.सा.-3 की गवाही का संबंध है, यह ऊपर उल्लिखित अन्य परिस्थितियों के साथ सबूत निर्धारित करता है।

12. ऐसा लगता है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक की भतीजी सुश्री माया को पेश नहीं करके अपनी समस्याओं को बढ़ा लिया है। सुश्री माया को पेश न करने का कारण मृतक की पत्नी से प्राप्त जानकारी बताई गई है कि सुश्री माया पक्षद्रोही हो गई थी। उसके पक्षद्रोही होने का सवाल तभी उठता जब वह गवाह के कठघरे में आती और अभियोजन पक्ष को उससे प्रतिपरीक्षा करने का लाभ मिलता। वही वह व्यक्ति थी जिसने घटना के बाद मृतक को अस्पताल पहुंचाया था और मृतक की देखभाल करने वाली पहली व्यक्ति थी। सुश्री माया को पेश नहीं करने के अभियोजन पक्ष के निर्णय ने इस प्रकार अपीलकर्ता के बचाव के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है।

13. उपरोक्त का परिणाम यह है कि अभियोजन पक्ष के मामले का एकमात्र आधार मृत्युकालिक कथन (प्र. अभि.सा.-15/डी) पर आधारित है।

14. अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जां.अधि. द्वारा अभिलिखित की गई मृत्युकालिक कथन अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय सबूत नहीं है क्योंकि अदालत ने जां.अधि. द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने पर नाराजगी जताई है। यह आगे बताया गया है कि हालांकि डॉक्टर ने 20.10.2003 को अपराह्न 4.10 बजे पर राय दी थी कि मृतक उन्मुख था और बयान देने की स्थिति में था, मृतक ने खुद इस तरह का बयान देने के लिए अपनी लाचारी व्यक्त की क्योंकि वह दर्द में था। उक्त बयान में मृतक की पत्नी, मृतक की भतीजी और अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति अभिलिखित की गई है, जिससे पता चलता है कि मृतक के मन को प्रभावित करने की

संभावना हमेशा बनी हुई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि इससे डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी संदेह पैदा करता है कि मृतक बयान देने के लिए सही स्थिति में था। जहाँ तक प्र. अभि.सा.-15/डी का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि बयान देने के लिए मृतक की चिकित्सा स्थिति के बारे में डॉक्टर से कोई नया प्रमाणन नहीं लिया गया था। इससे पहले 20.10.2003 को अपराह्न 4.10 बजे पर दिए गए प्रमाण पत्र का उपयोग 21.10.2003 को पूर्वाह्न 9:30 बजे बयान अभिलिखित करने के लिए नहीं किया जा सका, जिस अवधि के दौरान माना जा सकता है कि मृतक को शामक सहित दवाएं दी गई थीं। तथ्य यह है कि मृतक केवल 35 प्रतिशत जला हुआ था और फिर भी 21.10.2003 को उसकी मृत्यु हो गई थी, यह दर्शाता है कि मृतक की स्थिति दो दिनों से भी कम समय में बिगड़ गई थी।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि एम.एल.सी. (प्र. अभि.सा.-14/ए) के रूप में पहली मृत्युकालिक कथन में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेता है, हालांकि अपीलार्थी मृतक को जानते थे। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभि.सा.-15 का यह रुख कि उसने अपना बयान अभिलिखित करने से पहले डॉक्टर से मृतक की स्थिति के बारे में मौखिक रूप से पूछताछ की थी, अभि.सा.-17, डॉ. अभिषेक शर्मा की गवाही से गलत साबित होता है कि जां.अधि. ने प्रमाण पत्र प्र. अभि.सा.-17/ए प्राप्त करने के बाद उनसे संपर्क नहीं किया था। वह प्रमाण पत्र जां.अधि. द्वारा दायर आवेदन पर 20.10.2003 पर जारी किया गया था जो कि प्र.अभि.सा.-15/ए है। अभि.सा.-17 ने आगे कहा कि वह बयान अभिलिखित करते समय जां.अधि. के साथ नहीं थे और न ही उन्होंने मृतक का बयान अभिलिखित करते समय किसी भी चिकित्सा

कर्मचारी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। वह इस बात से भी अनजान था कि क्या गवाह के संबंध में अनुमति किसी अन्य स्रोत से मांगी गई थी।

16. अभि.सा.-15 की गवाही का हवाला देते हुए कहा गया था कि जब मृतक का बयान अभिलिखित किया गया था तो किसी भी मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया था और न ही गवाह को यह याद था कि ड्यूटी पर डॉक्टर कौन था। उन्हें पुलिस स्टेशन से प्रस्थान करते समय की गई डीडी प्रविष्टि का नंबर भी याद नहीं था और न ही दस्तावेजों की सूची में इसका उल्लेख था। यह कहने के बाद कि उसने मौखिक रूप से अनुमति प्राप्त की थी, गवाह ने कहा कि एक दिन पहले यानी 20.10.2003 पर डॉक्टर ने अपनी लिखित रिपोर्ट दी थी कि मृतक होश में और उन्मुख था। मृत्युकालिक कथन का कोई प्रमाणित गवाह नहीं है।

17. जहाँ तक अभि.सा.-2 श्रीमती सत्यभामा की गवाही का संबंध है, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यहां तक कि उनसे भी 10.11.2003 को देर से पूछताछ की गई थी और वह घटना की गवाह नहीं थीं। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने गणेश भवन पटेल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 4 एस.सी.सी. 371 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि जां.अधि. द्वारा एक चश्मदीद गवाह से पूछताछ करने में देरी अभियोजन मामले में गंभीर दुर्बलता के बराबर है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन किसी अन्य साक्ष्य के समान ही होता है और इसे आसपास की परिस्थितियों के आलोक में और साक्ष्य के महत्व को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। मृत्युकालिक कथन का विश्लेषण व्यक्ति की बताए गए तथ्यों को याद रखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या यह उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से

प्रभावित नहीं हुआ था। मृत्युकालिक कथन की इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गहन जांच की जानी चाहिए कि बयान अभियुक्त की अनुपस्थिति में दिया गया था, जिसे प्रतिपरीक्षा द्वारा बयान की सत्यता को परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं मिला था। जां.अधि. पर आरोप है कि उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन प्राप्त करने के मानदंड का पालन नहीं किया और इसके अलावा 21.10.2003 को बयान देने के लिए घोषणाकर्ता की स्वस्थता के संबंध में प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया।

18. विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम अध्याय 13-ए, खंड-III का उल्लेख निम्नलिखित प्रभाव के लिए किया हैः

> "1. किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के रूप में दिए गए बयान, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, स्वयं प्रासंगिक तथ्य हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत उन मामलों में साक्ष्य में स्वीकार्य हैं जिनमें व्यक्ति की मृत्यु के कारण पर प्रश्न उठता है। एक बयान जिसे आम तौर पर जाना जाता है-मृत्युकालिक कथन 'अपराधियों के मामले में इतना महत्वपूर्ण सबूत है कि सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप्स ने खुशाल बनाम बॉम्बे राज्य (ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 22) में फैसला सुनाया, जिसका पालन *सिंह बनाम राज्य* (ए.आई.आर. 1962 एस.सी.439) में किया गया था कि यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। अतः यह आवश्यक है कि मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय के समक्ष मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान का सही और विश्वसनीय रिकॉर्ड होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, मृत्युकालिक कथन को इसके बाद निर्धारित तरीके से अभिलिखित किया जाना चाहिए, और इसे करने वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जांच या विचारण में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. मृत्युकालिक कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अभिलिखित की जानी चाहिए—(i) वह व्यक्ति जिसका साक्ष्य आपराधिक आरोप के अभियोजन या कथित अपराध की उचित जांच के लिए आवश्यक है, जांच की कार्यवाही या मामले की विचारण शुरू होने से पहले मरने का खतरा है, यदि संभव हो तो उसका बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाए। जब मामले की जाँच से संबंधित पुलिस अधिकारी या ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने वाले चिकित्सा अधिकारी को पता चलता है कि मामला अदालत में रखे जाने से पहले ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का खतरा है, तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है, और उसकी अनुपस्थिति में, मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए मुख्यालय में मौजूद वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है।

(ii) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट तुरंत या तो स्वयं करेगा, या किसी अन्य वैतनिक न्यायिक मजिस्ट्रेट को मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा।

3. बयान देने के लिए घोषणाकर्ता की स्वस्थता की जांच की जानी चाहिए—मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने से पहले, न्यायिक मजिस्ट्रेट खुद को संतुष्ट करेगा कि घोषणाकर्ता बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में है, और यदि चिकित्सा अधिकारी मौजूद है, या उसकी उपस्थिति बिना समय गंवाए सुनिश्चित की जा सकती है, तो बयान देने के लिए घोषणाकर्ता की स्वस्थता के बारे में उसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ चिकित्सा अधिकारी की प्रतीक्षा या उपस्थिति की अनुमति नहीं देती हैं, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में मृत्युकालिक कथन तुरंत अभिलिखित कर सकता है, लेकिन उसे यह ध्यान देना चाहिए कि उसने डॉक्टर की उपस्थिति की प्रतीक्षा करना अव्यवहारिक या अनुचित क्यों माना।

... ...

7. पुलिस अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन का अभिलेखन—जहाँ पुलिस अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित की जाती है, वहाँ इसे, जहाँ तक संभव हो, उस समय मौजूद एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

8. बयान देने के लिए घोषणाकर्ता की स्वस्थता को न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए— न्यायिक मजिस्ट्रेट या मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाला अन्य अधिकारी मृत्युकालिक कथन के समापन पर यह प्रमाणित करेगा कि घोषणाकर्ता बयान देने के लिए उपयुक्त था और इसमें उसके द्वारा दिए गए बयान के साथ-साथ उन प्रश्नों का, यदि कोई हो, सही और विश्वसनीय रिकॉर्ड शामिल है, जो बयान अभिलिखित करने वाले न्यायाधीश द्वारा उनसे पूछे गए थे। यदि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के समय अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उपस्थित होता है, तो उसके द्वारा उठाई गई उसकी उपस्थिति और आपत्ति, यदि कोई हो, को न्यायिक मजिस्ट्रेट या मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाले अधिकारी द्वारा नोट किया जाएगा, लेकिन अभियुक्त का अधिवक्ता घोषणाकर्ता से प्रतिपरीक्षा करने का हकदार नहीं होगा।"

19. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, उपरोक्त सभी नियमों का उल्लंघन हुआ है।

20. अपीलकर्ताओं ने राज बहादुर बनाम राज्य; 45 (1991) डी.एल.टी. 144 (डी.बी.) में खण्ड पीठ की टिप्पणियों से बल प्राप्त करने की मांग की ताकि इस याचिका को आगे

बढ़ाया जा सके कि एक बार इंजेक्शन या शामक दिए जाने के बाद, मृतक की सामान्य जागरूकता बाधित हो सकती है।

21. इसके अलावा, कर्नाटक राज्य बनाम असलम उपनाम असलम पाशा में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ का फैसला; 2000 क्रि.लॉ.ज. 1167 पर भरोसा किया गया था जहां इसके पैरा 3 में निम्नानुसार देखा गया थाः

> "3. विद्वान राज्य लोक अभियोजक ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि एक अपवाद बनाया जा सकता है बशर्ते कि न्यायालय मौखिक साक्ष्य और शेष रिकॉर्ड से पूरी तरह से संतुष्ट हो कि अभिसाक्षी स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक स्थिति में था जो एक ठोस और सच्ची मृत्युकालिक कथन करने के लिए पर्याप्त था और जहां शेष रिकॉर्ड आम तौर पर संतोषजनक है, न्यायालय को इस आधार पर मृत्युकालिक कथन को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हम उन ठोस कारणों को दोहराने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि क्योंकि न्यायालय मृत्युकालिक कथन पर ही प्रमाणपत्र को अभिलेख करने पर जोर देता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह न्यायालय को इस तथ्य की कुछ गारंटी देता है कि प्रासंगिक समय पर, प्रभारी डॉक्टर ने अपना दिमाग लगाया है और रोगी की मृत्युकालिक कथन की सही क्षमता के बारे में प्रमाणित किया है। यह आवश्यकता सर्वविदित है और इसके बावजूद, वर्तमान मामला एकमात्र ऐसा नहीं है जिसमें हम पाते हैं कि यह त्रुटि की गई है। यह कुछ ऐसा है जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है और इसलिए, हम एक बार फिर यह दोहराना समान रूप से आवश्यक मानते हैं कि संबंधित विभाग को विशेष रूप से राज्य के सभी सार्वजनिक अस्पतालों और उन्हें संभालने वाले डॉक्टरों के ध्यान में लाना चाहिए कि प्रत्येक मामले में जहां मृत्युकालिक कथन अभिलिखित की आवश्यकता होती है यह जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और दूसरा, कि डॉक्टर को रोगी की

शारीरिक और मानसिक स्थिति का सही और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और मृत्युकालिक कथन पर ही प्रमाणित करना चाहिए, अगर डॉक्टर की राय में रोगी बयान देने के लिए अच्छी स्थिति में है। मूल्यांकन में प्राथमिक कारक जैसे रोगी की चेतना और दर्द, सदमे आदि को ध्यान में रखते हुए रोगी की मानसिक स्थिति के साथ-साथ जो भी दवाएं या दर्द निवारक दवाएं दी गई होंगी, उनके आलोक में रोगी की स्थिति भी शामिल होगी। प्रमाणपत्र को यंत्रवत रूप से जारी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सावधानीपूर्वक और गहन मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि मृत्युकालिक कथन बहुत मजबूत साक्ष्य है और सौ प्रतिशत वैध मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का आधार बन सकती है जबकि दूसरी ओर अभियुक्त को उसकी शुद्धता का परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि अभिसाक्षी पहले ही मर चुका है। हम चाहते हैं कि इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि किसी भी मामले में कोई गलती न हो और अगर ऐसा होता है तो लापरवाही या बेईमानी के कारण कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। विद्वान राज्य लोक अभियोजक इस आदेश की एक प्रति स्वास्थ्य सेवा निदेशक और सरकार के सचिव, स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजें कि दिशा-निर्देशों को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों को लिखित रूप में सूचित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी त्रुटियां न हों।"

22. <u>ताराचंद दामू सुतार बनाम महाराष्ट्र राज्य;</u> ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 130 मामले में उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया गया था कि मृत्युकालिक कथन पर केवल इसलिए विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त पर झूठा आरोप लगाने का कोई संभावित कारण नहीं दिया जा सकता है। इस पर तभी विश्वास किया जा सकता है जब इस पर संदेह करने का कोई आधार न हो।

23. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए आक्षेपित फैसले का समर्थन किया है कि मृत्युकालिक कथन पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।

24. आक्षेपित निर्णय को पढ़ने से हमें पता चलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय को इस तथ्य से तौला गया प्रतीत होता है कि निस्संदेह मृतक की मृत्यु मिट्टी का तेल डालने और उस पर जलती हुई माचिस डालने के कारण जलने से हुई थी। यदि अपीलार्थी ऐसा नहीं करते तो ऐसा कौन कर सकता था? इस प्रकार, इस प्रस्ताव पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करके काफी जोर दिया गया है कि न्याय प्रणाली टूट जाएगी और विश्वसनीयता खो देगी यदि इस सिद्धांत को चरम पर ले जाया जाता है कि भले ही हजारों दोषी छुट जाय, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए।

25. इसमें भी संदेह नहीं है कि मृत्यु की कगार पर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा की गई मृत्युकालिक कथन एक विशेष पवित्रता रखता है क्योंकि व्यक्ति के आसन्न मृत्यु की छाया में कोई भी असत्य बयान देने की संभावना बहुत ही कम होती है। यही कारण है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अनुसार मृत्युकालिक कथन को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि 'मरते हुए व्यक्ति के होठों पर सच्चाई होती है'। साथ ही, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन के मामले में, अभियुक्त को गवाह से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर नहीं मिलता है। मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है यदि यह न्यायालय के पूर्ण विश्वास को प्रेरित करता है और पुष्टि का नियम केवल विवेक का नियम है जैसा कि मुथु कुट्टी और अन्य बनाम राज्य; (2005) 9 एससीसी 113 में देखा गया है। मामले के तथ्यों में, डॉक्टर ने घोषणाकर्ता की स्थिति को प्रमाणित नहीं किया था, लेकिन मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के समय मौजूद डॉक्टर की गवाही अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए आई थी।

26. हम अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल पाते हैं कि मृत्युकालिक कथन संदेह से मुक्त नहीं है। डॉक्टर द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने, रोगी के होश में होने और उन्मुख होने का प्रमाण पत्र 20.10.2003 को अपराह्न 4.10 बजे दिया गया था। इस तथ्य के बावजूद, मृतक को कहानी का अपना पक्ष सुनाना संभव नहीं लगा क्योंकि वह दर्द में था। मृतक ने अपनी स्थिति बताते हुए 7 से 8 पंक्तियों का बयान दिया और कहा कि 20.10.2003 को एक घटना हुई थी, लेकिन कहा कि जब वह बेहतर महसूस करेंगे तो वह विवरण देंगे। अपीलार्थियों का नाम उन व्यक्तियों के रूप में नहीं लिया गया था जिन्होंने जघन्य कृत्य किया था। एम.एल.सी. (प्र. अभि.सा.-14/ए) ने अभिलिखित किया कि मृतक को मृतक की भतीजी सुश्री माया द्वारा अस्पताल लाया गया था, केवल तीन व्यक्तियों के बारे में बात करती है, लेकिन अपीलकर्ताओं का उल्लेख नहीं करती है, भले ही वे मृतक के पड़ोसी और ज्ञात व्यक्ति थे। मृत्युकालिक कथन (प्र. अभि.सा.-15/डी) को डॉक्टर से प्रमाणन प्राप्त किए बिना या डॉक्टर की उपस्थिति में 21.10.2003 को पूर्वाह्न 9:30 बजे पर अभिलिखित किया गया था। जां.अधि. ने दावा किया कि वह अकेले मौजूद थे। जां.अधि. ने मृतक का बयान अभिलिखित करने के लिए एस.डी.एम. या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति प्राप्त करने का ध्यान नहीं रखा क्योंकि आम तौर पर जां.अधि. द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए जब तक कि तथ्य ऐसे न हों कि देरी घातक हो सकती है। मृतक को शामक सहित विभिन्न दवाएं दी गईं थीं। जब बयान अभिलिखित किया जा रहा था तो मृतक की मानसिक स्थिति क्या होगी, यह एक सवालिया निशान बना हुआ है। जां.अधि. ने डॉक्टर की मौखिक सहमति प्राप्त करने का दावा किया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह भी

कहा कि लिखित सहमति पिछले दिन प्राप्त की गई थी। अभि.सा.-17, डॉक्टर ने इस बात से इनकार किया है कि 21.10.2003 को बयान अभिलिखित करने से पहले उनसे कभी मृतक की चिकित्सा स्थिति के बारे में पूछा गया था। मृतक की मृत्यु 21.10.2003 को अपराह्न 10.40 बजे हुई। केवल 35 प्रतिशत जले हुए मृतक ने दो दिनों के भीतर दम तोड़ दिया और इस प्रकार स्पष्ट रूप से उसकी हालत अच्छी नहीं थी और बिगड़ गई। एम.एल.सी. स्वयं अभिलिखित करता है कि उसकी स्थिति गंभीर थी और निर्जलीकरण (+ + +) था। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्ष्य के रूप में किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र या गवाह की उपस्थिति के बिना जां.अधि. द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करना संदेह से मुक्त नहीं होगा।

27. हम महसूस करते हैं कि वर्तमान मामला ऐसा है जहाँ जां.अधि. द्वारा जाँच को विफल कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष के मामले में मृत्युकालिक कथन को उचित तरीके से अभिलिखित करके और यह सुनिश्चित करके कि चश्मदीद गवाहों की गवाही तुरंत अभिलिखित की गई थी, दुर्बलताओं का आसानी से ध्यान रखा जा सकता था। मृतक की भतीजी सुश्री माया को पेश नहीं करने का कोई कारण नहीं था, जो मौके पर पहुंची और मृतक की पत्नी से मिली सूचना पर मृतक को अस्पताल ले गई कि वह पक्षविरोधी हो गई है। इसने अभियोजन पक्ष को सुश्री माया का प्रतिपरीक्षा करने के अवसर से वंचित कर दिया, भले ही वह पक्षविरोधी हो गई हो। अपीलार्थियों को लाभ केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने जिस तरह से मामले को आगे बढ़ाया है और हम मामले के जां.अधि. के आचरण की कड़ी निंदा करते हैं। हमारे पास अपील की अनुमति देने और अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

28. अपीलार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

संजय किशन कौल, न्या.

25 सितंबर, 2009 अजीत भरीहोक, न्या.
डीएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकदमेंबाजी के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*